नूर मोहम्मद

वी

जेठानंद और एक अन्य

(2011 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 25848)29 जनवरी, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100 द्वितीय अपील-न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग-विवाद का देरी से विचारण- बार-बार स्थगन के कारण विलम्ब-मामले से निपटने के लिए सम्यक श्रम का प्रदर्षन न करना-प्रतिकूलता-अभिनिर्धारित-शीघ्र न्याय प्रदत्त करना संवैधानिक आदेष है-विवाद की प्रकृति चाहे जो भी हो शीघ्र् और उचित चित्रण न्यायिक कर्त्तवय के लिए मौलिक है- कानून की अदालत में किसी विवाद का विलंबित वर्णन न्याय के मानक वितरण और अंतिम परिणाम में सेंध लगाता है परिणामस्वरूप बैंच और बार धीरे-धीरे अपनी श्रद्धा खो देते है क्योंकि देवत्व व कुलीनता की भावना वास्तव में संस्थागत सेवा क्षमता से प्रवाहित होती है-एक लोकतांत्रिक निकाय में राजनीति एक लिखित संविधान द्वारा शासित होती है और जहां विधि का शासन सर्वोपरि है वहां न्यायपालिका को न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को देखने के लिए भी तत्पर प्रहरी के रूप में

माना जाता है सम्मान किया जाता है और संवैधानिक व्यवस्था में लोगों का विष्वास और आषा कम नहीं होती है- वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय को मामले को स्थगित करके इतनी बडी उदारता नहीं दिखानी चाहिए थी जब अपीलकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। यह कल्पना करना मुष्किल है कि अदालत ने अपीलकर्ता को नये सिरे से नोटिस देने का निर्देष क्यों दिया जबकि ऐसा आदेष पारित करने के लिए कुछ भी सुझाव नहीं था- वकील ने लापरवाहीपूर्वक एक के बाद एक स्थगन की मांग की और उसे रूटीन तरीके से स्थगन दिये गये-वकील का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के अधिकारी के रूप में उचित रूप से तैयारी कर न्यायालय की सहायता करे न कि अनावष्यक स्थगन की मांग करे। न्याय वितरण प्रणाली में शामिल सभी लोगों जिनमें न्यायाधीष वकील न्यायालयों में कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारी राज्य के विधि अधिकारी रजिस्ट्री और वादी शामिल है को समर्पित परिश्रम दिखाना होगा ताकि विवाद को शांत किया जा सके। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष को मामलों की प्रथमिकता को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में अत्यधिक देरी से बचने के लिए एक सिस्टम की कल्पना करने और अपनाने की आवष्यकता है जिन्हें वास्तव में शीघ्रता से निपटाया जा सकता है-न्यायपालिका

प्रत्यर्थी-वादी ने निषेधाज्ञा का वाद दायर किया जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया अपील में आदेष बरकरार रखा गया। सन्इ 2001 में प्रत्यर्थी ने द्वितीय अपील दायर की जो मुख्य रूप से वकील की

गैर हाजिरी के कारण स्थगन से लम्बे समय तक लम्बित रही। दूसरी अपील अंततः वर्ष 2003 में गैर-अभियोजन के कारण उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। सन् 2006 में द्वितीय अपील को पुनः बहाल किया गया जबकि बहाली का मंत्रालयिक आदेष 2010 में दर्ज किया गया। अन्ततः: वर्ष 2011 में विधि के दो महत्वपूर्ण प्रष्नों पर द्वितीय अपील एडमिट की गई और निचली दोनों अदालतों के फेसले और डिक्री पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेष के द्वारा रोक लगा दी गई-

याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रष्न अपील में शामिल नहीं था और उच्च न्यायालय के पास तथ्यात्मक स्कोर के आधार पर दूसरी अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं था।

न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया -

1-1 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के आदेष में हस्तक्षेप करने की कोई आवष्यकता नहीं है लेकिन जिस परेषान करने वाले तरीके से द्वितीय अपील में कार्यवाही जारी रही उसके सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से कुछ कहने की आवष्यकता है (पैरा-10½ ¼1159 सी-डी½

1-2 उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील की कार्यवाही उस विनाषकारी प्रभाव का प्रतीक है जो प्रभाव स्थगन का मुकदमेबाजी पर हो सकता है कि कैसे एक लिस एक ऑक्टोपस के जाल में फंस सकता है। न्याय का दर्षन एक वकील और अदालत की भूमिका, एक वादी का दायित्व और सभी विधायी आदेष बेंच और बार की कुलीनता सभी सम्बन्धितों की क्षमता और दक्षता और अंततः कानून की दिव्यता की संभावना है। वर्तमान प्रकृति की देरी होने पर उदासीनता और उदासीनता का रास्ता किसी की ओर से विलम्ब जीवन के मूल्यों को नष्ट कर देता है और कानून की पवित्रता में एक भयावह अषांति पैदा करता है। न्यायनिर्णयन को स्थगन के द्वारा और मामले के निपटाने के लिए सम्यक परिश्रम का प्रदर्षन न करने के द्वारा पंगु बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी व्यक्ति उस समय की आवष्यक भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। अनन्त धेर्य की अपेक्षा करना विनाषकारी है। दृष्टिकोण में बदलाव आज का वारंट और आदेष है। ¼ पैरा 11½ ¼1159-ई-एच 1160-ए ½

1-3. कानून का शासन केन्द्रापसारक चिंता का विषय है और मामलों के परिसीमन और निपटान में देरी एक कृत्रिम वायरस को जन्म देती है और एक विघ्नकारी तत्व बन जाती हैA स्थानिक देरी की दुर्भाग्यपूर्ण विशेषताओं से किसी भी कीमत पर बचना होगा।मुकदमेबाजी की प्रकृति जो

भी हो शीघ्र और उचित चित्रण न्यायिक कर्तव्य का मौलिक है।[पैरा 12,23] [1160-सी-डी;1166-सी-डी]

1-4 अतीत में व्यक्त की गई पीड़ा और न्यायाधीशों वकीलों और वादियों की भूमिका निरंतर चिंता का विषय है और इसे हर पल प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। उदासीनता के रवैये की न तो सराहना की जा सकती है और न ही इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए संस्था की सेवाक्षमता का महत्व बढ़ जाता है।यह कानून के महामहिम का आदेश है और किसी को भी इसमें अंतराल पैदा करने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए। टालमटोल चाहे व्यक्तिगत हो या संस्थागत स्तर पर एक प्रणालीगत विकार है।इसका क्षरणकारी प्रभाव एवं असाध्य एवं तीव्र गति से बढ़ने वाली घातक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक ढांचे की अव्यवस्थित स्थिति के समान है। अदालत के पदाधिकारियों या बार के सदस्यों द्वारा देरी काफी हद तक आलस्य को दर्शाती है।[पैरा 27] [1167-C-E]

1-5 एक लोकतांत्रिक निकाय की राजनीति में जो एक लिखित संविधान द्वारा शासित होती है और जहां कानून का शासन सर्वोपरि हैA न्यायपालिका को न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बल्कि यह देखने के लिए भी प्रहरी माना जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्य इसमें निहित हैं। संविधान का सम्मान किया जाता है और संवैधानिक व्यवस्था

में लोगों का विश्वास और आशा कम नहीं होती है।लोकतंत्र की मूल अवधारणा को केवल एक विशाल और अमूल्य खजाने के रूप में संरक्षित किया जा सकता हैA जहां न्याय के गुण और मूल्य सर्वोच्च होते हैं और बौद्धिक एनीमिया को निरंतर धैर्य निरंतर दृढ़ता और तर्कपूर्ण सतर्कता द्वारा दूर रखा जाता है।न्याय की बुनियाद अन्य बातों के अलावा अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण पर टिकी है।यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह न्याय की प्राथमिक नैतिकता और न्यायपालिका की नैतिक धुरी है।कानून की अदालत में किसी विवाद का विलंबित चित्रण न्याय की मानक व्यवस्था में सेंध लगाता है और अंततः बेंच और बार धीरे-धीरे अपनी श्रद्धा खो देते हैं क्योंकि देवत्व और बड़प्पन का भाव वास्तव में संस्थागत सेवाशीलता से आता है।इसलिए ऐतिहासिक रूप से न्याय प्रशासन करते समय एक निर्णायक की व्यक्तिगत संस्थावाद और सामूहिक संस्थागतवाद पर जोर दिया गया है।बिना किसी विरोधाभास के डर के यह कहा जा सकता है कि सामूहिक lkewfgdrk को कभी भी न्याय के त्वरित वितरण के लिए एक विदेशी अवधारणा नहीं माना जा सकता है। यही कर्तव्य की पहचान है और यही वास्तविक माप है।[Para

1] [1154-E-F, H; 1155-A-D]

1-6 एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली में आंतरिक और अंतर्निहित विश्वास मौलिक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।देरी से

व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास धीरे-धीरे कम हो जाता है। आस्था और विश्वास ही व्यवस्था को जीवित रखता है।आस्था के विखंडन में प्रलय की स्थिति लाने की क्षमता होती है, जहां न्याय एक दुर्घटना बन सकता है।एक वादी एक संयमी न्यायाधीश से तर्कसंगत फैसले की उम्मीद करता है, लेकिन उसका इरादा कारणों की बलिवेदी पर ज्यादा समय बर्बाद करने का नहीं होता है और यह सही भी है। समय पर न्याय मिलने से विश्वास कायम रहता है और सतत स्थिरता स्थापित होती है।त्वरित न्याय को एक मानव अधिकार माना जाता है जो लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा में गहराई से निहित है और ऐसा अधिकार न केवल कानून का निर्माण है बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार भी है।व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों की अपेक्षित प्रतिबद्धता से यह अधिकार पूरी तरह से विकसित हो सकता है। इसे यूटोपियनवाद का प्रतीक नहीं माना जा सकता क्योंकि इस तरह के विचार से उद्देश्य की केंद्रीयता खोकर अधिकार को मृगतृष्णा बनाने की संभावना है।इसलिए न्याय वितरण प्रणाली में जिसकी भी भूमिका हो, उसे दूर-दूर तक आकस्मिक दृष्टिकोण की कल्पना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (पैरा ई 29] [1168-सी-एफ]

1-7 न्याय प्रदान करने की प्रणाली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता में आम आदमी के विश्वास को प्रेरित करना होगा। विश्वास के निर्वाह को सहानुभूति या भोग के बिना रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाना चाहिए।यदि कोई कार्य को अत्यंत कठिन

मानता है तो उसे गंभीरता से करना होगा क्योंकि विश्वास हमारे सिस्टम का एलन वाइटल है। [पैरा31) [1169-एफ-जी]

1-8 मौजूदा मामले में दूसरी अपील की प्रस्तुति की तारीख से प्रवेश की तारीख तक उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की बात करें तो जिस तरह से यह आगे बढ़ी है वह न केवल हैरान करने वाली है बल्कि चौंकाने वाली भी है।जब अपीलकर्ता का वकील मौजूद नहीं था तो अदालत को मामले को स्थगित करके इतनी बड़ी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी।यह कल्पना करना मुश्किल है कि अदालत ने अपीलकर्ता को नए सिरे से नोटिस देने का निर्देश क्यों दिया जबकि ऐसा आदेश पारित करने के लिए कुछ भी सुझाव नहीं था।इस मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा लेकर निपटाया जाना चाहिए था। यह भी आश्चर्यजनक है कि वकीलों ने नियमित तरीके से स्थगन की मांग की और अदालत ने ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी कर लिया।जब मामला खारिज हो गया तो बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था फिर भी इसे लंबे समय के बाद सूचीबद्ध किया गया था। परेशानी और बढ़ गई tc संबंधित अधिकारी ने फ़ाइल को व्यवस्थित करने में अपना समय लिया।रजिस्ट्रार जनरल की और से से यह स्पष्ट है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन वह दूसरी बात है इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मामले से निपटने में भारी देरी हुई है। यदि समय पर प्रयास किया गया होता और उचित चिंता व्यक्त की गई होती तो

इसे टाला जा सकता था।ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां देरी अपरिहार्य हो सकती है। लेकिन मौजूदा मामले में वकील ने लापरवाही से स्थगन के बाद स्थगन की मांग की और उसे नियमित तरीके से मंजूरी दे दी गई। अदालत के अधिकारी के रूप में वकील का यह कर्तव्य है कि वह उचित तरीके से अदालत की सहायता करे और अनावश्यक स्थगन की मांग न करे। स्थगन प्राप्त करना न्यायालयों द्वारा कभी भी सराहा नहीं गया है। न्याय वितरण प्रणाली में शामिल सभी लोगों को जिनमें न्यायाधीश वकील अदालतों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारी राज्य के कानून अधिकारी रजिस्ट्री और वादी शामिल हैं, को समर्पित परिश्रम दिखाना होगा ताकि विवाद 'kkar हो सके। दोष मढ़ना इलाज नहीं है. जिम्मेदारी स्वीकार करना और सीमा पर एक कप्तान की तरह उससे निपटना समय की मांग है। परिश्रम से संतुष्टि मिलती है जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए।सभी संबंधितों को आलस्य को त्यागने और खुद को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि देरी का सिंड्रोम शीघ्र न्याय प्रदान करने की अवधारणा को नष्ट न कर दे जो कि संवैधानिक आदेश है। विचलन की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति और उसके निवारण के लिए उठाए गए आवश्यक कदम एक उज्ज्वल दीपक होंगे जो धीरे-धीरे एक लेजर किरण बन जाएंगे। यह lHkh की अपेक्षा है और उक्त अपेक्षा को वास्तविकता बनना होगा। अपेक्षाओं को आशा के स्तर पर नहीं रहना है। उन्हें वास्तविकता में

रूपांतरित करना होगा। [पैरा 32] [1169-जी-एच; 1170-सी ए-एच; 1171-ए-सी]

1-9 हालाँकि यह अदालत कोई भी निर्देश जारी ugha dj jgh gS क्योंकि एक संवैधानिक अदालत के रूप में mPp U;k;ky; को बोझ उठाना होगा और वादियों की अपेक्षित अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा।वकील समुदाय से भी यह अपेक्षा की जाती है कि देरी से बचा जाए। सम्मिलित प्रयास का परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध है कि वे मामलों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए एक तंत्र की कल्पना करें और उसे अपनाएं, ताकि उन मामलों में ऐसी अत्यधिक देरी से बचा जा सके जिन्हें वास्तव में f'k?kz <ax ls निपटाया जा सकता है।

कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य (2005) 4 एससीसी 480: 2005 (3) एससीआर 289; सुशी/कुमार सेन बनाम बिहार राज्य (1975) 1एफ एससीसी 774: 1975 (3) एससीआर 942; पंजाब राज्य बनाम शामलालमुरारी (1976) 1 एससीसी 719: 1976 (2) एससीआर 82; टॉपलाइन जूते लिमिटेड बनाम निगम. बैंक (2002) 6 एससीसी 33: 2002 (3) एससीआर 1167;शिव कोटेक्स बनाम तिर्गुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2011) 9 एससीसी 678: 2011 (10) एससीआर 787; रेमन सेवाएँ जी प्रा. लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर और

अन्य एआईआर 2001 एससी 207:2000 (4) सप्ल. एससीआर 550; महाबीर प्रसाद सिंह बनाम जैक एविएशन प्रा. लिमिटेड एआईआर 1999 एससी 287: 1998 '(2) पूरक। एससीआर 675; पांडुरंग दत्तात्रय खांडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे और अन्य (1984) 2 एससीसी 556: 1984 एच (1) एससीआर 414; लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी बनाम राज्य (दिल्ली)।नूर मोहम्मद बनाम जेठानंद 1153 प्रशासन, प्रशासन) एटीआर 1.984 एससी 618: 1984 (2) एससीआर 438; ओ.पी. एशार्न्ट.ए; और अन्य, वी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय(201·आरटी);:;.6 एससीसी 86: 20,1 (&) एससीआर 301; आर.के. गर्ग, अधिवक्तावी. हिमाचल प्रदेश राज्य (1981) 3 सेकंड 166: 1981 (3)एससीआर 536; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, राज्यबिहार एआईआर 1979 एससी 1360: 1979 (3) एससीआर 169; हुसैनारा खातून (चतुर्थ) और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य,पटना (1980) 1 एससीसी 98: 1979 (3) एससीआर 532; दीवान नौबत राय एवं अन्य बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन के माध्यम से ए.आई.आर 1989 एससी 542: 1989 (1) एससीसी 297; सुरिंदर सिंह बनाम राज्य पंजाब (2005) 7 एससीसी 387: 2005 (2) सप्ल। एससीआर 1172; सीरामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य (2001) 5 एससीसी 714: 2001 (3) एससीआर 669 और जाहिरा हबीबुल्फा एच।शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 एससीसी 158: 2004 (3) एससीआर 1050 - संदर्भित।कोर्ट में मेरा

जीवन (गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क: डबलडे और डीकंपनी इंक., 1961) हेज़र लुईस द्वारा; पृ.213 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

2005 (3) एससीआर 289	संदर्भित	पैरा 13
1975 (3) एससीआर 942	संदर्भित	पैरा 13
1976 (2) एससीआर 82	संदर्भित	पैरा 13
2002 (3) एससीआर 1167	संदर्भित	पैरा 14
2011 (10) एससीआर 787	संदर्भित	पैरा 15
2000 (4) सप्ल. एससीआर 550	संदर्भित	पैरा 16
1998 (2) पूरक। एससीआर 675	संदर्भित	पैरा 16
1984 (1) एससीआर 414	संदर्भित	पैरा 18
1984 (2) एससीआर 438 को	संदर्भित	पैरा 19
2011 (6) एससीआर 301	संदर्भित	पैरा 21
1981 (3) एससीआर 536	संदर्भित	पैरा 22
1979 (3) एससीआर 169	संदर्भित	पैरा 24
1979 (3) एससीआर 532	संदर्भित	पैरा 24
1989 (1) धारा 297	संदर्भित	पैरा 25
2005 (2) पूरक। एससीआर 1172	संदर्भित	पैरा 26
2001 (3) एससीआर 669	संदर्भित	पैरा 30
2004 (3) एससीआर 1050	संदर्भित	पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: एसएलपी संख्या (सी) संख्या 2011 का 25848

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 09-05-2011 से एसबी सिविल द्वितीय अपील क्रमांक 2001 का 207

न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जे. का निर्णय पारित किया गया

एक लोकतांत्रिक निकाय की राजनीति में जो एक लिखित संविधान द्वारा शासित होती है और जहां कानून का शासन सर्वोपरि है, न्यायपालिका को न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बल्कि यह भी देखने के लिए प्रहरी के रूप में माना जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्य इसमें निहित हैं। संविधान का सम्मान किया जाता है और संवैधानिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास और आशा कम नहीं होती है।कानून के शासन की पवित्रता न तो एक स्वामी और एक दास को पहचानती है और न ही एक शासक और एक प्रजा की कल्पना करती है, बल्कि, सर्वोत्कृष्टता में, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों की महिमा में गाती है और कानून के अनुसार वर्तमान पीढ़ी से अपेक्षा करती है। सभी प्रभावों को त्याग कर भावी पीढ़ी के लिए उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी है।लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सामूहिकता के प्रत्येक सदस्य द्वारा निरंतर बलिदान एक स्पष्ट अनिवार्यता है।लोकतंत्र की मौलिक अवधारणा को केवल एक विशाल और अमूल्य खजाने के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जहां न्याय के गुण और मूल्य सर्वोच्च होते हैं और बौद्धिक एनीमिया को निरंतर धैर्य, निरंतर दृढ़ता और तर्कपूर्ण सतर्कता द्वारा दूर रखा जाता है।न्याय की बुनियाद अन्य बातों के अलावा अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण पर टिकी है।यह कहना अतिशयोक्ति

नहीं होगी कि यह न्याय की प्राथमिक नैतिकता और न्यायपालिका की नैतिक धुरी है।इसकी गहनता इसमें है कि किसी भी चीज को उसे पंगु बनाने या ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाए जो उसे स्थिर कर दे या उसे नपुंसकता का शिकार बना दे।कानून की अदालत में किसी विवाद का विलंबित चित्रण न्याय के मानक वितरण में सेंध लगाता है और अंततः, बेंच और बार धीरे-धीरे अपनी श्रद्धा खो देते हैं, क्योंकि देवत्व और बड़प्पन की भावना वास्तव में संस्थागत सेवाक्षमता से बहती है।इसलिए, ऐतिहासिक रूप से, न्याय प्रशासन करते समय एक निर्णायक की व्यक्तिगत संस्थावाद और सामूहिक संस्थागतवाद पर जोर दिया गया है।बिना किसी विरोधाभास के डर के यह कहा जा सकता है कि सामूहिक सामूहिकता को कभी भी न्याय के त्वरित वितरण के लिए एक विदेशी अवधारणा नहीं माना जा सकता है।यही कर्तव्य की पहचान है, और यही वास्तविक उपाय है।

2. वर्तमान में तथ्यात्मक सांचा के लिए प्रतिवादी ने 1990 से एक सिविल वाद नंबर 42 को दायर करके सिविल कार्रवाई शुरू की, ताकि प्रतिवादी को घर के दक्षिणी हिस्से की ओर की वादग्रस्त जमीन को बेचने या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जा सके और उसे जमीन पर कोई भी निर्माण करने से स्थायी रूप से रोका जा सके। लिखित बयान दाखिल होने के बाद, प्रतिवादी द्वारा एक प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया।इसके बाद, विवाद्यक तय किए गए और पार्टियों ने अपने-अपने पक्ष को साबित करने के लिए सबूत पेश किए। 12.9.1997 को, विद्वान सिविल जज

(जूनियर डिवीजन) नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान ने मुकदमे को खारिज कर दिया और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी दावे पर फैसला सुनाया। उपरोक्त निर्णय और डिक्री से दुखी होकर, पहले प्रतिवादी ने संबंधित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नोहर की अदालत में 1997 की सिविल प्रथम अपील संख्या 59 दायर की, जिसने 10.07.2001 को अपील खारिज कर दी।अपील खरिज होने से प्रतिवादी को राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल द्वितीय अपील संख्या 207/2001 दायर करने के लिए मजबूर होना पडा।

3. यह ध्यान दिया जाये कि, हमने तथ्यात्मक विवाद और उस पर आए निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि हमारे उद्देश्य के लिए उस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

4. दूसरी अपील का उतार-चढ़ाव भरा दुखद इतिहास, 27.7.2011 को शुरू हुआ, जब अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।अपील को 30.07.2001 को स्थगन आवेदन के साथ दर्ज होने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने कैविएट दर्ज की थी और वह दर्ज होने की तारीख पर उपस्थित था और दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रार्थना के आधार पर, अदालत ने निचली अदालतों के अभिलेख मांगे। इसके बाद, मामला 8.11.2001, 5.12.2001 और 18.1.2002 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन पार्टियों के वकीलों की गैर-उपस्थिति के कारण कोई आदेश

पारित नहीं किया गया था।18.2.2002 को, हालांकि अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था, फिर भी अदालत ने अपील स्थगित कर दी।इसी प्रकार, 20.01.2003 और 4.2.2003 को वकील की अनुपस्थिति में स्थगन दिया गया था।यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब अपील 4.2.2003 को सूचीबद्ध की गई, तो अदालत ने अपीलकर्ता को अपने प्रतिनिधित्व के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। यह नोट करना उचित होगा कि प्रतिवादी के वकील उस दिन उपस्थित थे।इसके बाद, अपीलकर्ता को नोटिस की तामील की प्रतीक्षा में मामले को कई बार स्थगित किया गया।नोटिस की सेवा पूरी होने के बाद, मामला 23.9.2003 को सूचीबद्ध किया गया था और, हमेशा की तरह, अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था।7.10.2003 को भी ऐसी ही समान स्थिति थी.10.11.2003 को, जब अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था, तो प्रतिवादी के वकील की उपस्थिति में अभियोजन न चलाने के कारण अपील खारिज कर दी गई।

5. अभियोजन के अभाव में अपील खारिज होने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता नींद से जागा और 2004 में बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे अंततः 9.1.2006 के आदेश के तहत अनुमति दी गई।जैसा कि ऑर्डर शीट से पता चलता है, समय छह साल से अधिक समय तक बेहोशी के बाद आखिरकार, 11.5.2010 को बहाली का मंत्रालयिक आदेश दर्ज किया गया।समय की कृत्रिम रुकावट को तोड़ते हुए

बहाली की औपचारिकता पूरी होने के बाद, जब फ़ाइल एक बड़े अजगर की तरह घूम गई, तो अपील को 25.10.2010 को स्वीकार करने के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिस दिन अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने बहस शुरू की और अंततः स्थगन की मांग की. मामला 10.11.2010 तक स्थगित कर दिया गया।इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा आदेश 41, नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ सपठित धारा 100 (5) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और प्रतिवादी, वादी के वकील को उसी और मामले का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था। दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।आदेशिका से और पर्दा हट जाएगा, कि अपील 29.11.2010 को फिर से सूचीबद्ध की गई और इस बीच, प्रतिवादी ने सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

6. जब मामला प्रवेश के लिए दिनांक २४-०२-२०११ को सूचीबद्ध किया गया था तब न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामला प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और सभी आवेदनों पर उस तिथि पर विचार किया जाएगा। 7.3.2011 को, अदालत द्वारा मामले को एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया क्योंकि स्थगन मांगा गया था। स्थगन के लिए इसी तरह की प्रार्थना 16.3.2011 को की गई थी और मामले को प्रार्थना के अनुसार दो सप्ताह के बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

गया था। 27.04.2011 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"अपीलकर्ता के लिए कोई नहीं।

मैंने रिकार्ड का अवलोकन किया है।यह दूसरी अपील वर्ष 2001 में दायर की गई थी और अब 10 साल से अधिक समय हो गया है, इसे अभी तक अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें धारा 100 के आश्य के अनुसार कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या नहीं।.इससे मेरी अंतरात्मा को निस्संदेह गंभीर चिंता हुई है कि इस अपील पर यह निर्णय लेने में दस साल लग गए कि क्या इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

पिछले दस वर्षों में वकील को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कारण की परवाह किए बिना और केवल मात्र अनुरोध पर मामले को लगभग हर अवसर पर स्थगित किया जा रहा है।

आज भी अपीलकर्ता के वकील उपस्थित नहीं हुए हैं।एक अन्य वकील ने खड़े होकर कहा कि जो वकील नियुक्त किया गया है वह स्वस्थ नहीं है, इसलिए मामले को स्थगित कर दिया जाए। अभियोजन के अभाव में मैं अपील खारिज कर सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होता।अत्यधिक अनिच्छा के साथ और अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध और अपीलकर्ता को सुनवाई का अधिकार

देने के लिए पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से, मैं वकील को समायोजित करने के लिए मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य हूं (हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए) और प्रवेश के लिए अपील को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करना चाहिए ।

7. अंत में, 9.5.2011 को, दोनों पक्षों के विद्वान वकील उपस्थित हुए और मामले को कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वीकार कर लिया गया और निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एचडी थानवी ने तर्क दिया है कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था और उच्च न्यायालय के पास केवल तथ्यात्मक कारणों के आधार पर दूसरी अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं था।

9. जब मामला 21.9.2012 को हमारे समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

> "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2001 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई दूसरी अपील को 10.11.2003 को अभियोजन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में जनवरी, 2006 में फाइल करने के लिए बहाल कर दिया गया और दूसरी अपील दायर

करने के लगभग 10 साल बाद, दोनों निचले न्यायालयों के फैसले और डिक्री को उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 9.5.2011 के द्वारा रोक दिया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के भीतर एसबी सिविल द्वितीय अपील संख्या 207 की सन 2001 से 2011 तक की प्रगति का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

10. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रार जनरल ने इस न्यायालय को एक रिपोर्ट पे्रिषत की है जिसके आधार पर हमने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया है।इस स्टेज पर, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने विपक्षी प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं किया था क्योंकि हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।लेकिन, भाव रूप से, दूसरी अपील में जिस तरह से कार्यवाही जारी रही, वह परेशान करने वाली है जो हमें उक्त विषय पर कुछ कहने के लिए मजबूर करती है।ऐसा नहीं है कि यह न्यायालय पहली बार यह कह रहा है, परन्तु एक अनुस्मारक गहन आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता है और आवश्यक सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील की कार्यवाही, यदि हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो उस विनाशकारी प्रभाव का प्रतीक है जो स्थगन का मुकदमेबाजी पर हो सकता है और कैसे एक लिस एक ऑक्टोपस के जाल में फंस सकता है। न्याय का दर्शन, एक वकील और अदालत की भूमिका, एक वादी का दायित्व और सभी विधायी आदेश, बेंच और बार की कुलीनता, सभी संबंधितों की क्षमता और दक्षता और अंततः कानून की दिव्यता बनाने की संभावना है वर्तमान प्रकृति की देरी होने पर उदासीनता और उदासीनता का रास्ता, किसी की ओर से विलंब जीवन के मूल्यों को नष्ट कर देता है और कानून की पवित्रता में एक भयावह अशांति पैदा करता है।मामले से निपटने के लिए स्थगन और उचित परिश्रम का प्रदर्शन न करने से न्यायनिर्णयन के गुणों को पंगु बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कोई भी व्यक्ति समय की अनुभूति संबंधी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता।कोई भी आइवरी टावर में बैठने का जोखिम नहीं उठा सकता।न तो कोई न्यायाधीश और न ही कोई वकील "ब्रह्मांड के पूर्ण दबाव और दबाव" को नजरअंदाज कर सकता है।अनंत धैर्य की अपेक्षा करना विनाशकारी है।दृष्टिकोण में बदलाव आज का वारंट और आदेश है।हम लाभ के लिए याद कर सकते हैं कि जस्टिस कार्डोज़ो ने क्या कहा था:

"मुझे लगता है कि यह सच है कि आज कानून के हर विभाग में किसी नियम का सामाजिक मूल्य बढ़ती शक्ति और महत्व की कसौटी बन गया है।"

12. यह ध्यान में रखना होगा कि फुर्सत के समय को शालीनता से दफ़नाना होगा.यह जितनी जल्दी ऐसा हो उतना अच्छा है.यह वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वह समय के साथ चले और हर पल खुद को याद दिलाए कि कानून का शासन केन्द्रापसारक चिंता का विषय है और मामलों के आलेखन और निपटारे में देरी एक कृत्रिम वायरस को जन्म देती है और एक विघ्नकारी तत्व बन जाती है। स्थानिक देरी की दुर्भाग्यपूर्ण विशेषताओं से किसी भी कीमत पर बचना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यही वह दिन है, यही वह समय है और यही वह क्षण है, जब सभी सिपाही कानून के रास्ते से लड़ते हैं।व्यक्ति को अपने आप को उस महान कहावत की याद दिलानी होगी, "जागो, उठो, 'हे' पार्थ"।

13. जैसा कि सलाह दी गई है, वर्तमान में, हम इस न्यायालय की कुछ घोषणाओं का संदर्भ लेने के लिए तैयार हैं। कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य[1] मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे से निपटते समय

कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम 1 अनिवार्य है या निर्देशिका है,सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य में टिप्पणियों का उल्लेख किया। 2] जिसे हम लाभप्रद रूप से पुनरुत्पादित कर सकते हैं: -

> "कानून के हाथों न्याय की नश्वरता एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और कानून सुधारक पर क्रोधपूर्ण सवाल उठाती है।
>
> प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों पर इस तरह से हावी है कि वह मूल अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी हो जाता है। मानवतावादी नियम यह है कि प्रक्रिया कानूनी न्याय की दासी होनी चाहिए, मालकिन नहीं, न्यायाधीशों को एक्स डेबिटो जस्टिसिया के रूप में कार्य करने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, जहां अन्यथा दुखद परिणाम पूरी तरह से असमान होगा।...न्याय न्यायशास्त्र का लक्ष्य है - प्रक्रियात्मक, उतना ही वास्तविक।" बेंच ने विशेषण कानून की प्रक्रिया से संबंधित दृष्टिकोण पर जोर देने के लिएपंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी [3] के फैसले का भी उल्लेख किया ।उक्त मामले में कहा गया है:-

"प्रक्रियात्मक कानून अत्याचारी नहीं बल्कि सेवक है, बाधा नहीं बल्कि न्याय में सहायता है।प्रक्रियात्मक नुस्खे दासी हैं, स्वामिनी नहीं, स्नेहक हैं, न्याय प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं।"

14. हम सुविधा के लिए नोट कर सकते हैं कि न्यायालय ने आगे कहा था कि प्रक्रिया निर्देशिका है लेकिन वांछनीयता की अवधारणा पर जोर दिया गया था और उपरोक्त उद्देश्य के लिए, टॉपलाइन शूज़ लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन बैंक का संदर्भ दिया गया था [4].इसके पीछे के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए, तीन-न्यायाधीश-पीठ ने टॉपलाइन शूज़ लिमिटेड (सुप्रा) का उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहा: -

"36.न्यायालय ने आगे कहा कि प्रावधान ऐसे विवादों के त्वरित निपटान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के माध्यम और अधिक है।जिन कठोर शर्तों में प्रावधान शामिल है, वे "वांछनीयता" की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन देरी के कारण शिकायतकर्ता के पक्ष में किसी भी प्रकार का ठोस अधिकार नहीं बनाते हैं, ताकि प्रतिवादी को किसी भी परिस्थिति में बचाव में अपना पक्ष रखने से रोका जा सके।"

15. शिव कोटेक्स बनाम तिर्गुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में [5] यह न्यायालय दूसरी अपील में उच्च

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार कर रहा था जिसमें उच्च न्यायालय ने कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया था और आगे की अनुमति दी थी वादी द्वारा केवल इस आधार पर अपील की गई कि दांव ऊंचे थे और बिना किसी सबूत के वादी को गैर-अनुकूलित किया जाना चाहिए था।इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विवाद्यक तय होने और मामले को तीन मौकों पर वादी के साक्ष्य पेश करने के लिए तय किए जाने के बाद, वादी ने सबूत पेश नहीं करने का विकल्प चुना। न्यायालय द्वारा पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित प्रभाव वाला था: -

> "क्या अदालत केवल इसलिए स्थगन पर स्थगन देने के लिए बाध्य है क्योंकि विवाद में बहुत कुछ दांव पर लगा है? क्या अदालत को मूक दर्शक बने रहना चाहिए और मामले का नियंत्रण उस पक्ष के हाथ में छोड़ देना चाहिए जिसने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है?"इसके बाद, न्यायालय ने इस प्रकार उत्तर दिया: -
>
> "15. यह दुखद है, लेकिन सच है कि मुकदमेबाज़ स्थगन की मांग करते हैं - और अदालतें तुरंत स्थगन दे देती हैं। ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश थोड़ा सक्रिय होते हैं और अनावश्यक स्थगन के अनुरोधों को स्वीकार करने से इनकार

करते हैं, मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए वादी सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सिविल विवाद लगातार खिंचते रहते हैं।अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा अनुचित सहानुभूति और अनुग्रह इस बीमारी को और अधिक बढ़ा देता है।जो मामला सामने आया है वह ऐसी ही गलत सहानुभूति का मामला है। अब समय आ गया है कि अदालतें न्याय वितरण प्रणाली में देरी के प्रति संवेदनशील हो जाएं और महसूस करें कि स्थगन न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता को नुकसान पहुंचाते हैं और यदि इस खतरे को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया गया, तो मुकदमेबाज जनता जल्द ही सिस्टम में विश्वास खो सकती है।अदालतों, विशेषकर निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर मुकदमे में प्रभावी प्रगति हो।

16. किसी भी वादी को सीपीसी में प्रदान की गई प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है।स्थगन कैंसर की तरह बढ़ गया है और न्याय वितरण प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है।''इतना कहने के बाद, बेंच ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

"मुकदमे का एक पक्ष अपने अवकाश और आनंद से मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है और उसे यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसके द्वारा सबूत कब दिए जाएंगे या मामले की सुनवाई कब की जानी चाहिए। मुकदमे के पक्षकारों - चाहे वादी हो या प्रतिवादी - को सुनवाई की तारीख, जिसके लिए मामला तय किया गया है, पर प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने में अदालत के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं।"

16. रेमन सर्विसेज प्राइवेट में लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर और अन्य[6],महाबीर प्रसाद सिंह बनाम जैक्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के एक अंश का हवाला देते हुए । न्यायालय ने इस प्रकार आगाह किया: -

"फिर भी हमने पेशे को यह ध्यान में रखा है कि भविष्य में यदि गैर-उपस्थिति केवल हड़ताल के आह्वान के आधार पर होती है, तो वकील पक्ष भी भुगतने वाले परिणाम के लिए जवाब देह होगा।यह अन्यायपूर्ण और असमान है कि अकेले पक्ष को अपने वकील के स्वयं लगाए गए अपमान के लिए पीड़ित होना पड़े। हम आगे यह भी जोड़ सकते हैं कि जो वादी अपने वकील के अदालत में उपस्थित न होने के कारण पूरी तरह से पीड़ित होता है, उसके पास वकील पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का भी उपाय है, लेकिन वह उपाय इस मामले में अपनाए गए पाठ्यक्रम से अप्रभावित रहेगा।फिर भी, इस तरह की स्थितियों में, जब न्यायालय अपने

वकील के उपस्थित न होने पर पार्टी पर जुर्माना लगाता है, तो हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि उसी न्यायालय के पास पक्ष को संबंधित वकील से लागत वसूलने की अनुमति देने की शक्ति है। हालाँकि, ऐसा निर्देश वकील को अवसर देने के बाद ही पारित किया जा सकता है।यदि उसके पास कोई उचित कारण है तो न्यायालय निश्चित रूप से उसे ऐसे दायित्व से मुक्त कर सकता है।"

17. ध्यान दें, हालांकि उक्त अनुच्छेद वकीलों की हड़ताल के संदर्भ में कहा गया था, फिर भी इसका जोर अदालत में एक वकील द्वारा गैर-उपस्थिति पर है।

18. इस संदर्भ में, हम पांडुरंग दत्तात्रय खांडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे और अन्य के फैसले का ८ उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने देखा कि एक वकील वादियों के प्रति लोको पेरेंटिस में खड़ा होता है और इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राहक निःस्वार्थ, ईमानदार और ईमानदार उपचार प्राप्त करने का हकदार है, खासकर जहां ग्राहक जरूरत के समय सहायता के लिए अधिवक्ताओं के पास जाता है।

19. लेफ्टिनेंट एसजे चौधरी बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)[9] मामले में, एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने, एक आपराधिक मुकदमे में एक वकील की भूमिका से निपटते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"हम याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव की गई कठिनाई की सराहना करने में असमर्थ हैं। इसमें कहा गया है कि उनके वकील को दिन-प्रतिदिन अदालत में उपस्थित होने में कठिनाई हो रही है। यह प्रत्येक वकील का कर्तव्य है, जो एक आपराधिक मामले में दिन-प्रतिदिन मुकदमे में भाग लेने के लिए ब्रीफ स्वीकार करता है।हम दिन-प्रतिदिन मुकदमे में भाग लेने के लिए वकील के कर्तव्य पर अधिक जोर नहीं दे सकते।संक्षिप्त विवरण स्वीकार करने के बाद, यदि वह उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह अपने पेशेवर कर्तव्य का उल्लंघन करेगा।

20. महाबीर प्रसाद सिंह (सुप्रा) मामले में, खंडपीठ ने न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य में एक वकील के दायित्व और बार के प्रति न्यायालय के कर्तव्य पर जोर देते हुए निम्नानुसार फैसला सुनाया है: -

> "एक वकील का दायित्व है कि वह ऐसा कुछ भी न करे जिससे उस न्यायालय की गरिमा कम हो, जिसका वह स्वयं एक शपथ अधिकारी और सहायक है।उसे हर समय न्यायाधीश के प्रति सम्मानजनक सम्मान देना चाहिए और अदालत कक्ष की मर्यादा का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।(वेयरवेल्स लीगल एथिक्स पृष्ठ 182 पर) बेशक, यह एकतरफा मामला नहीं है।न्यायालय का भी पारस्परिक कर्तव्य है कि वह बार के सदस्यों के प्रति विनम्र रहे और

उस सम्मान को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करे जो बार के सदस्य अपने ग्राहकों के साथ-साथ वादी जनता से पाने के हकदार हैं।बेंच और बार दोनों न्यायिक मंच के दो अविभाज्य विंग हैं और इसलिए कानून के न्यायालयों में किए जाने वाले गंभीर कार्यों के कुशल कामकाज के लिए उपरोक्त पारस्परिक सम्मान अनिवार्य है।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वकील या उनका समूह अदालतों या किसी विशेष अदालत का बहिष्कार कर सकता है और अदालत को न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए कह सकता है।किसी भी दर पर, कोई भी वकील अदालत से इस आधार पर किसी मामले को टालने के लिए नहीं कह सकता है कि वह उस अदालत में पेश नहीं होना चाहता है।"

21. कानूनी पेशे का सदस्य होने के नाते, न्यायालय और समाज के प्रति एक वकील के कर्तव्यों को दोहराते हुए,ओपी शर्मा और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस न्यायालय ने देखा है कि वकील की भूमिका और स्थिति संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत की शुरुआत में वकीलों को यह तय करने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है कि देश का प्रशासन कानून के शासन द्वारा शासित होना चाहिए।पीठ ने संविधान निर्माण में प्रख्यात वकीलों की भूमिका पर जोर दिया।इस अवधारणा पर

भी जोर दिया गया कि न्याय प्रशासन में वकील न्यायालय के अधिकारी होते हैं।

22. आरके गर्ग, एडवोकेट बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य[11] में, चंद्रचूड़, सीजे, ने बेंच और बार के बीच संबंधों के संबंध में न्यायालय के लिए बोलते हुए, इस प्रकार राय दी: -

> "....बार और बेंच एक ही तंत्र का अभिन्न अंग हैं जो लोगों को न्याय प्रदान करते हैं।बेंच के कई सदस्य बार से आते हैं और उनका पिछला जुड़ाव उनके लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत है।यह बार के लिए समान रूप से गर्व का विषय होना चाहिए।यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि शिष्टाचार शिष्टाचार को जन्म देता है और जिस प्रकार दान की शुरुआत घर से होती है, शिष्टाचार की शुरुआत न्यायाधीश से होनी चाहिए। एक असभ्य न्यायाधीश अदालत कक्ष की सेटिंग में एक खराब उपकरण की तरह है।लेकिन बार के सदस्यों को यह याद रखना होगा कि पेशेवर नैतिकता और सुसंस्कृत आचरण के ऐसे घोर उल्लंघन का परिणाम केवल उस प्रणाली का अंतिम विनाश होगा जिसके बिना कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है।

23. हमने उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख केवल इस उद्देश्य से किया है कि न्यायालय ने, विभिन्न संदर्भों में, स्थगन की बीमारी से निपटा था और अपनी पीड़ा व्यक्त की थी।मुकदमेबाजी की प्रकृति जो भी हो, त्वरित और उचित चित्रण न्यायिक कर्तव्य का मौलिकता है।हालांकि आपराधिक मुकदमे के संबंध में न्याय वितरण प्रणाली में देरी पर टिप्पणी करते हुए, कृष्णा अय्यर, जे. ने इस प्रकार कहा था: -

> "हमारी न्याय प्रणाली, गंभीर मामलों में भी, धीमी गति सिंड्रोम से ग्रस्त है जो "निष्पक्ष सुनवाई" के लिए घातक है, चाहे अंतिम निर्णय कुछ भी हो। त्वरित न्याय सामाजिक न्याय का एक घटक है क्योंकि समग्र रूप से समुदाय इस बात से चिंतित है कि अपराधी को उचित समय के भीतर उचित सजा दी जाए और निर्दोष को आपराधिक कार्यवाही की कठिन परीक्षा से मुक्त कर दिया जाए।"

24. आपराधिक न्यायशास्त्र में, शीघ्र सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21का एक अविभाज्य घटक बन गया है और इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि त्वरित सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है (देखें हुसैनारा खातून) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य[12],हुसैनारा खातून (चतुर्थ) और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना[13])।

25. दीवान नौबत राय और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन के माध्यम से राज्य[14] में, यह राय दी गई है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार परीक्षण के सभी चरणों, अर्थात् जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील और पुनरीक्षण को शामिल करता है।

26. सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [15] में, यह दोहराया गया है कि त्वरित सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक विस्तार और सामग्री में निहित है।इस प्रकार, इसे चरम पर रखा गया है और यह हर किसी की जिम्मेदारी बनती है जिसे ओलंपियन शांति के साथ निभाना होगा।

27. अतीत में व्यक्त की गई पीड़ा और न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों की भूमिका निरंतर चिंता का विषय है और इसे हर पल प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।उदासीनता के रवैये की न तो सराहना की जा सकती है और न ही इसे बर्दाश्त किया जा सकता है।इसलिए, संस्था की सेवाक्षमता का महत्व बढ़ जाता है।यह कानून के महामहिम का आदेश है और किसी को भी इसमें अंतराल पैदा करने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए।टालमटोल, चाहे व्यक्तिगत हो या संस्थागत स्तर पर, एक प्रणालीगत विकार है।इसका क्षरणकारी प्रभाव एवं प्रभाव असाध्य एवं तीव्र गति से बढ़ने वाली घातक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक ढांचे की अव्यवस्थित स्थिति के समान है।अदालत के पदाधिकारियों या बार के

सदस्यों द्वारा की गई देरी काफी हद तक आलस्य को दर्शाती है और कोई भी साठथ वेल की एक पंक्ति उधार लेते हुए कह सकता है, "रेंगने वाले घोंघे में सबसे कमजोर ताकत होती है"।पाँच दशक से कुछ अधिक समय पहले, वकीलों की ज़िम्मेदारी के बारे में बात करते हुए, नाइज़र लुईस[16] ने इस प्रकार कहा था: -

> "मैं मानता हूं कि परेशान ग्राहक को शांति और आत्मविश्वास दिलाना एक वकील का काम है।कानून कार्यालय में आने वाला लगभग हर व्यक्ति किसी समस्या से भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है।यह केवल दबाव झेलने की डिग्री और ग्राहक के आंतरिक संसाधनों की बात है।"

28. प्रसिद्ध फ्रैंकफर्टर की कुछ पंक्तियाँ दोहराना उपयोगी है:

> "मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में एक प्रैक्टिसिंग वकील के अलावा और कुछ नहीं है, वह समाज के जीवन में एक बहुत ही महान और आवश्यक कार्य पूरा करता है। सही मायने में वकील बनने के लिए एक तरफ जिम्मेदारियों और दूसरी तरफ संतुष्टि के बारे में सोचें।"

29. एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायिक प्रणाली में आंतरिक और अंतर्निहित विश्वास मौलिक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।देरी से व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास धीरे-धीरे कम हो जाता है।आस्था और

विश्वास ही व्यवस्था को जीवित रखता है।यह लगातार ऑक्सीजन प्रदान करता है।आस्था के विखंडन में प्रलय की स्थिति लाने की प्रभाव-क्षमता होती है जहां न्याय दुर्घटना बन सकता है।एक वादी एक संयमी न्यायाधीश से तर्कसंगत फैसले की उम्मीद करता है, लेकिन उसका इरादा कारणों की बलिवेदी पर ज्यादा समय बर्बाद करने का नहीं होता है और यह सही भी है।समय पर न्याय मिलने से विश्वास कायम रहता है और सतत स्थिरता स्थापित होती है।त्वरित न्याय तक पहुंच को एक मानव अधिकार माना जाता है जो लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा में गहराई से निहित है और ऐसा अधिकार न केवल कानून का निर्माण है बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार भी है।व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों की अपेक्षित प्रतिबद्धता से यह अधिकार पूरी तरह से विकसित हो सकता है।इसे यूटोपियनवाद का एक पहलू नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा विचार उद्देश्य की केंद्रीयता को खोकर अधिकार को मृगतृष्णा बना देगा। इसलिए, न्याय वितरण प्रणाली में जिसकी भी भूमिका हो, उसे दूर-दूर तक आकस्मिक दृष्टिकोण की कल्पना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

30. इस संदर्भ में, रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य[17]के एक अंश का उल्लेख करना उपयुक्त है : -

> "22.. कुछ गवाहों के साक्ष्य में, विशेष रूप से विशेष अनुमति याचिका के चरण में, ढीली सजा का लाभ उठाकर,

कल्पनाशील और मनगढ़ंत आधारों का सहारा लेकर न्यायिक प्रणाली को फिरौती की ओर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कानून निर्णयों की अंतिमता पर जोर देता है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने से अधिक चिंतित है।न्यायालयों को न्याय प्रशासन के साथ सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।कोई भी प्रयास जो व्यवस्था को कमजोर करता है और न्याय वितरण प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को हिलाता है, उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

31.जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य[18] मामले में, न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के न्यायालय के कर्तव्य पर जोर देते हुए, इस न्यायालय ने मार्मिक रूप से इस प्रकार कहा है: -

"35....न्यायालयों को हमेशा न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखना एक सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है - जिसे अक्सर "कानून की महिमा" को साबित करने और बनाए रखने के कर्तव्य के रूप में जाना जाता है।न्याय के समुचित प्रशासन को हमेशा एक सतत प्रक्रिया के रूप में

देखा गया है, जो किसी विशेष मामले के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, भविष्य में कानून की अदालत के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता की रक्षा करता है जैसा कि पहले के मामले में था।इस प्रकार, उपरोक्त से, यह दिन की तरह स्पष्ट है कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता में आम आदमी के विश्वास को प्रेरित करना होगा।विश्वास के निर्वाह को सहानुभूति या भोग के बिना रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाना चाहिए।यदि कोई कार्य को अत्यंत कठिन मानता है, तो उसे गंभीरता से करना होगा, क्योंकि विश्वास हमारे सिस्टम का 'एलन वाइटल' है।

32. दूसरी अपील की प्रस्तुति की तारीख से प्रवेश की तारीख तक उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की बात करें तो जिस तरह से यह आगे बढ़ी है वह न केवल हैरान करने वाली है बल्कि चौंकाने वाली भी है।हम यह सोचने में इच्छुक हैं कि जब अपीलकर्ता के वकील मौजूद नहीं थे तो अदालत को मामले को स्थगित करके इतनी बड़ी उदारता नहीं दिखानी चाहिए थी।यह कल्पना करना मुश्किल है कि अदालत ने अपीलकर्ता को नए सिरे से नोटिस देने का निर्देश क्यों दिया, जबकि इस तरह का आदेश पारित करने के लिए कुछ भी सुझाव नहीं था।इस मामले को

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा लेकर निपटाया जाना चाहिए था।यह भी आश्चर्यजनक है कि वकीलों ने नियमित तरीके से स्थगन की मांग की और अदालत ने ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी कर लिया।जब मामला खारिज हो गया, तो बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, फिर भी इसे लंबे समय के बाद सूचीबद्ध किया गया था।परेशानी और बढ़ गई, संबंधित अधिकारी ने फ़ाइल को व्यवस्थित करने में अपना समय लिया।रजिस्ट्रार जनरल के पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।वह अलग बात है और उस संबंध में हमारा कुछ भी कहने का इरादा नहीं है.लेकिन जिस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह यह है कि मामले से निपटने में भारी देरी हुई है।यदि समय पर प्रयास किया गया होता और उचित चिंता व्यक्त की गई होती तो इसे टाला जा सकता था। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां देरी अपरिहार्य हो सकती है।हमारा इरादा उदाहरण देने का नहीं है, क्योंकि उक्त मामलों में तथ्य खुद ही बोल देंगे।मौजूदा मामले में, जैसा कि हम समझ रहे हैं, विद्वान वकील ने लापरवाही भरे तरीके से एक के बाद एक स्थगन की मांग की और उसे नियमित तरीके से मंजूरी दे दी गई।अदालत के अधिकारी के रूप में वकील का यह कर्तव्य है कि वह उचित तरीके से अदालत की सहायता करे और अनावश्यक स्थगन की मांग न

करे।स्थगन प्राप्त करना न तो कला है और न ही विज्ञान।न्यायालयों द्वारा इसकी कभी सराहना नहीं की गयी।न्याय वितरण प्रणाली में शामिल सभी लोगों को, जिनमें न्यायाधीश, वकील, अदालतों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारी, राज्य के कानून अधिकारी, रजिस्ट्री और वादी शामिल हैं, को समर्पित परिश्रम दिखाना होगा ताकि विवाद खड़ा हो सके। आराम करने के लिए।दोष मढ़ना इलाज नहीं है.जिम्मेदारी स्वीकार करना और सीमा पर एक कसान की तरह उससे निपटना समय की मांग है।यह कहना उचित होगा कि परिश्रम से संतुष्टि मिलती है।मन में जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।एक समय आ गया है जब सभी संबंधित लोगों को आलस्य को त्यागने और खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना है कि देरी का सिंड्रोम शीघ्र न्याय प्रदान करने की अवधारणा को नष्ट न कर दे जो कि संवैधानिक आदेश है।विचलन की विवेकपूर्ण स्वीकृति और उसके निवारण के लिए उठाए गए आवश्यक कदम एक उज्ज्वल दीपक होंगे जो धीरे-धीरे एक लेजर किरण बन जाएंगे।यह सामूहिकता की अपेक्षा है, और उक्त अपेक्षा को वास्तविकता बनना होगा।अपेक्षाओं को आशा के स्तर पर नहीं रहना है।उन्हें वास्तविकता में रूपांतरित करना होगा।बहुत पहले, फ्रांसिस बेकन ने अपनी कहावत शैली में

कहा था, "आशा अच्छा नाश्ता है, लेकिन यह ख़राब रात्रिभोज है"। हम इस संबंध में और कुछ नहीं कहते।

33. यद्यपि हमने इस मुद्दे पर विचार किया है, फिर भी हम कोई भी निर्देश जारी करने से बचते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को बोझ उठाना होगा और वादियों की अपेक्षित अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा।वकील समुदाय से भी यह अपेक्षा की जाती है कि देरी से बचा जाए।सम्मिलित प्रयास का परिणाम अवश्य मिलेगा।इसलिए, हम राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य विद्वान मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं कि वे मामलों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए एक तंत्र की कल्पना करें और उसे अपनाएं, ताकि उन मामलों में ऐसी अत्यधिक देरी से बचा जा सके जिन्हें वास्तव में निपटाया जा सकता है। शीघ्रता से.एक कदम आगे बढ़ाना मंजिल की ओर एक कदम है।एक समझदार व्यक्तिगत प्रेरणा और एक प्रतिबद्ध सामूहिक प्रयास निस्संदेह इस संबंध में मदद करेगा।न कम, न ज़्यादा.

34. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।

[1] (2005) 4 एससीसी 480

[2] (1975) 1 एससीसी 774

[3] (1976) 1 एससीसी 719

[4] (2002) 6 एससीसी 33

[5] (2011) 9 एससीसी 678

[6] एआईआर 2001 एससी 207

[7] एआईआर 1999 एससी 287

[8] (1984) 2 एससीसी 556

[9] एआईआर 1984 एससी 618

[10] (2011) 6 एससीसी 86

[11] (1981) 3 एससीसी 166

[12] एआईआर 1979 एससी 1360

[13] (1980) 1 एससीसी 98

[14] एआईआर 1989 एससी 542

[15] (2005) 7 एससीसी 387

[16] 1961) पृष्ठ 213 [17] (2001)

5 एससीसी 714 [18] (2004)

4 एससीसी 158

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पावन कुमार वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।